RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 167
दि. 16.10.2025, गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.
Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में शत प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में शत प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय सरकार की पूर्व सैनिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वीकृत बढ़ोतरी इस प्रकार हैं:

पेनुरी ग्रांट को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस कदम से 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्ध और गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों तथा उनकी वीर नारियों को आजीवन आर्थिक सुरक्षा व निरंतर सहायता

सुनिश्चित होगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है। इसके अलावा, दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही वीर नारियों के लिए शिक्षा अनुदान को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति कर दिया गया है, जिससे शिक्षा के अवसरों को और सशक्त सहयोग मिलेगा।

विवाह अनुदान को प्रति लाभार्थी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। यह संशोधित अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह और वीर नारियों के पुनर्विवाह पर लागू होगा, बशर्ते ये विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुए हों।

संशोधित दरें 1 नवंबर, 2025 से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगी। इन संशोधनों से सरकार पर लगभग 257 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा, जिसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) से वहन किया जाएगा।

इन योजनाओं का वित्तपोषण रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है, जो एएफएफडीएफ का एक उपकोष है और पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित है।

यह निर्णय गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और निम्न आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा के ताने-बाने को सशक्त बनाता है। साथ ही, यह देश के पूर्व सैनिकों की सेवा, समर्पण एवं बलिदान के प्रति सरकार की अटूट सम्मानभावना और प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

'एकजुट एनडीए-एकजुट बिहार' पीएम मोदी ने दिया बिहार चुनाव का नारा, कहा- घर-घर पहुंचाएं बूथ वर्कर्स

पीएम मोदी ने नया नारा दिया कि 'एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, फिर से बनेगी सुशासन की सरकार'.

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 'एकजुट NDA, एकजुट बिहार, फिर से बनेगी सुशासन की सरकार'का नारा दिया है. उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हर बूथ और हर घर तक पहुंचने की हिदायत दी. उन्होंने बूथ वर्कर्स को सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर घर जाएं और केंद्र एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दें. उन्होंने ये यहां नया नारा दिया कि 'एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, फिर से बनेगी सुशासन की सरकार'. अब देखना ये है कि बिहार में ये नारा क्या रंग लाता है. बूथ वर्कर्स हर बूथ को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने इलाके के हर

को इस नारे को हर किसी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से चुनावी राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए ये भी जोर दिया कि परिवार को उपलब्ध सरकारी लाभ और योजनाओं के बारे में जानकारी दें. कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने कई वाक्य भोजपुरी में भी बोले. लोगों को वीडियो दिखाएं और शेयर करेंए मोदी ने भोजपुरी में कार्यकर्ताओं से कहा कि 'जब हर बूथ मजबूत होगा, तभी पार्टी जीतती है'. पीएम ने ये भी कहा कि 'हर बूथ वर्कर अपने क्षेत्र में मोदी हैं' और उन्हें मतदाताओं को सरकारी योजनाओं के बारे में अपनी तरफ से गारंटी देने के लिए कहा.उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि बिहार के बूथ वर्कर्स परिवारों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के वीडियो दिखाएं और साझा करें.

मैथिली को मिला टिकट

बीजेपी ने बुधवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की जिसमें 12 उम्मीदवार शामिल हैं. अलीनगर सीट से गायक मैथिली ठाकुर और बक्सर से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है. बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को राष्ट्रमंडल संघ द्वारा मंजूरी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को राष्ट्रमंडल संघ द्वारा मंजूरी दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की

यह भारत को विश्व खेल मानचित्र पर स्थापित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों का एक शानदार प्रमाण है

विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण और देशभर में खेल प्रतिभाओं का एक पूल तैयार कर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को एक अद्भुत खेल डेस्टिनेशन बना दिया है

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की

मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को राष्ट्रमंडल संघ द्वारा मंजूरी दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज भारत के लिए अपार हर्ष और गौरव का दिन है। उन्होंने राष्ट्रमंडल संघ द्वारा अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मंजूरी दिए जाने पर भारत के प्रत्येक नागरिक को हार्दिक बधाई दी। श्री शाह ने कहा कि यह भारत को विश्व खेल मानचित्र पर स्थापित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों का एक शानदार प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण और देशभर में खेल प्रतिभाओं का एक विशाल पूल तैयार कर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को एक अद्भुत खेल डेस्टिनेशन बना दिया है।

रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति श्री गेराल्डो अल्कमिन से मुलाकात की। इस बैठक में ब्राजील के रक्षा मंत्री श्री जोस

म्यूसियो मोंटेइरो फिल्हो भी उपस्थित थे।

नेताओं ने वर्तमान में जारी रक्षा संबंधी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की और रक्षा उपकरणों के सह-विकास एवं सह-उत्पादन के अवसरों की खोज सहित संयुक्त कार्य के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की

दिवाली पर सीएम योगी का डबल गिफ्ट, मुफ्त गैस सिलेंडर और दंगाइयों को कड़ा संदेश

सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा, "कोई भी त्यौहार के रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी

लखनऊ, .(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों के मौसम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को एक तरफ बड़े तोहफे दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ कानून-व्यवस्था को लेकर कड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने महिलाओं को दिवाली का खास तोहफा दिया और साफ कहा कि शांति भंग करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुले हैं.

मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर की सौगात

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले 1.86 करोड़ परिवारों (विशेषकर गरीब और वंचित महिलाओं) को यह

तोहफा दिया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार अब साल में दो बार ये सिलेंडर मुफ्त देगी. जिस रसोई गैस के लिए जनता को पैसे देने होते हैं, यूपी सरकार अब साल में ऐसे दो सिलेंडर मुफ्त देगी.

सीएम योगी बोले- अगर किसी को यमराज के दर्शन करने हों तो किसी बेटी को छेड़ने की हिम्मत करें

कड़े दिशा-निर्देश

सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा, "कोई भी त्यौहार के रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी. कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी." उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे त्यौहार शांति और सौहार्द से मनाएं.

महिलाओं की सेफ्टी पर जोर

महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने अपराधियों को सख्त संदेश दिया.

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की लायंस क्लब के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ गांधीनगर में बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता से सेमीकंडक्टर तक सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक नेतृत्व के फलस्वरूप भारत की ग्लोबल इमेज में वृद्धि हुई है
- प्रधानमंत्री की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सबका साथ-सबका विकास' की राजनीति से विश्व के देशों में भारत के प्रति विश्वास दृढ़ हुआ है

गांधीनगर, 15 अक्टूबर : लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में आयोजित इस मुलाकात-बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता से लेकर सेमीकंडक्टर तक सभी क्षेत्रों के

विकास को प्राथमिकता दी है। इसके फलस्वरूप देश विकास के नित-नए शिखर पार कर रहा है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक नेतृत्व के परिणामस्वरूप भारत की ग्लोबल इमेज में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सबका साथ-सबका विकास' की जो राजनीति दी है, उससे विश्व के देशों में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने लायंस क्लब की विश्वभर के देशों में सेवाभावी संस्था के रूप में उपस्थिति की प्रशंसा की और संस्था को उसके विकासोन्मुखी कार्यों में राज्य सरकार के उचित सहयोग का भी आश्वासन दिया।

उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू कराए गए अभियानों से आ रहे परिवर्तनों की भूमिका दी और लायंस क्लब द्वारा सरकार के अभियानों में सक्रिय भागीदारी की भी सराहना की।

भारत और सऊदी अरब ने रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में सहयोग मजबूत किया

(जीएनएस)।

भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग और सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज मंत्रालय के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग की सचिव सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा ने किया। सऊदी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उद्योग एवं खनिज उप मंत्री इंजीनियर खलील बिन इब्राहिम बिन सलामाह ने किया।

सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 41.88 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है जिसमें रसायन और पेट्रोकेमिकल्स का योगदान 10 प्रतिशत अर्थात 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर है।

बैठक के दौरान हुई चर्चा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने तथा रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों को तलाशने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मद्यनिषेद्य विभाग, उ0प्र0 द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में नशा मुक्त भारत अभियान, राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन सम्पन्न

मद्यनिषेद्य विभाग, उ0प्र0 द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत दिनांकः 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार / विशेष कार्यक्रमों का विवरण-

वाईकेके

दिनांकः 15 अक्टूबर 2025 को नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत शताब्दी प्रेक्षागृह, कृषि विज्ञान संस्थान, बी०एच०यू० में मद्यनिषेध विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा छात्र अधिष्ठाता, छात्र कल्याण संकाय, बी०एच०यू के सहयोग से नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरुकता हेतु मद्यनिषेध प्रदर्शनी, संगोष्ठी सहित विभिन्न प्रकार के शिक्षात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में श्री नितिन अग्रवाल, माननीय मंत्री आबकारी एवं मद्यनिषेध विभाग, उ०प्र० की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय कुलपति महोदय प्रो0 अजीत कुमार चतुवेर्दी द्वारा की गयी।

सर्वप्रथम माननीय मंत्री आबकारी एवं मद्यनिषेध विभाग, उ०प्र० एवं अन्य

गणमान्य अतिथियों द्वारा मद्यनिषेध प्रदर्शनी का उदघाटन एवं अवलोकन किया गया तदोपरान्त मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यापर्ण कर माननीय मंत्री जी के करकमलों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन करते हुए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। श्री आर0एल0 राजवंशी, राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ॰प्र॰ द्वारा परिचयात्मक उदबोधन में विभाग की उपलब्धियों के साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में अवगत कराया गया।

माननीय मंत्री श्री नितिन अग्रवाल, आबकारी एवं मद्यनिषेध विभाग, उ॰प्र॰ द्वारा प्रदेश के युवाओं में नशे की बढती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए जनमानस से अपील की गयी नशा मुक्त भारत अभियान व एक युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम को गति प्रदान करने की आवश्यकता है। इस कार्य में शासकीय प्रयासों के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत विजन 2047 के नशा मुक्त भारत अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु पूर्ण मनोयोग से योगदान देने हेतु प्रेरित किया। प्रो॰ अजीत कुमार चतुवेर्दी, कुलपति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग रोकथाम व जनजागरुकता हेतु युवाओं की सहभागिता के संबंध में प्रकाश डाला गया। प्रो॰ अनुपम कुमार नेमा, छात्र अधिष्ठाता, छात्र कल्याण संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग, कारण व समाधान पर बहुआयामी दृष्टिकोण से चर्चा किया गया।

वडोदरा मंडल द्वारा त्योहारी सीजन 2025 के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू

यात्रियों की बढ़ती संख या के मद्देनजर सुरक्षित और व्यवस्थित त्योहारी यात्रा सुनिश्चित करने हेतु वड़ोदरा मंडल की सक्रिय तैयारी

आगामी त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ और यात्रियों की आवाजाही में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम रेलवे के वड़ोदरा मंडल द्वारा सुरक्षित, सुचारू और कुशल रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधा उपाय शुरू किए गए हैं। वडोदरा एवं प्रतापनगर स्टेशनों अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गई है।

श्री अनुभव सक्सेना, जनसंपर्क अधिकारी, वडोदरा मंडल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वडोदरा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक निर्दिष्ट यात्री होल्डिंग क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें यात्रिओं के लिए बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल सुविधा, पर्याप्त रोशनी, पंखे और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसी आवश्यक यात्री सुविधाएं प्रदान की गयी है।

वडोदरा और प्रतापनगर स्टेशनों पर यात्री प्रवेश और टिकट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त बुकिंग काउंटर चालू किए गए हैं।

प्रत्येक स्टेशन पर कतार नियमन, यात्री सहायता और उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टिकट जांच कर्मचारियों और आरपीएफ कर्मियों की तैनाती भी की गयी है।

श्री सक्सेना ने आगे बताया कि ट्रेन के प्रस्थान से पहले प्रतीक्षारत यात्रियों को आराम से बैठाने के लिए वडोदरा स्टेशन पर पर्याप्त कवर्ड होल्डिंग क्षमता बनाई गई है। समर्पित होल्डिंग एरिया के रूप में प्लेटफार्म संख्या 6 के निकट 300 वर्ग मीटर से अधिक के सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की गई है।

रेलवे सुरक्षा बल (फ्ढक्र) के जवान प्रभावी समन्वय बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ड्यूटी के दौरान निर्बाध डिजिटल संचार के लिए वॉकी-टॉकी और बॉडी वॉर्न कैमरा का उपयोग कर रहें हैं। फ्ढक्र द्वारा सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी तथा यात्रियों की आवाजाही पर चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक समय पर समन्वय और किसी भी स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए प्रभागीय नियंत्रण कार्यालय में एक समर्पित युद्ध कक्ष स्थापित किया गया है।

पश्चिमी रेलवे का वडोदरा डिवीजन यात्रियों से अपील करता है कि वे प्लेटफॉर्म या प्रवेश द्वार के पास भीड़ लगाने के बजाय निर्धारित होल्डिंग एरिया का उपयोग करें, ताकि व्यस्त समय के दौरान आवाजाही को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सके। यात्रियों से यह भी आग्रह किया जाता है कि वे ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के दिशानिर्देशों का पालन करें, क्योंकि ये व्यवस्थाएं सभी यात्रियों की सुरक्षा, आराम और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए की गई हैं।

अहमदाबाद मंडल के आंबलियासन-विजापुर रेलखंड का गेज परिवर्तन कार्य पूर्ण

42.32 किमी लंबा खंड अब ब्रॉड गेज में परिवर्तित, 16 एवं 17 अक्टूबर 2025 को होगा संरक्षा निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के आंबलियासन-विजापुर रेलखंड (42.32 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब यह खंड मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित होकर यात्रियों के लिए आधुनिक और सुरक्षित परिचालन के लिए तैयार है। इस खंड का संरक्षा निरीक्षण रेल संरक्षा आयुक्त (CRS), पश्चिम रेलवे द्वारा 16 एवं 17 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा, जिसमें 16 एवं 17 अक्टूबर को मोटर ट्रॉली निरीक्षण तथा 17 अक्टूबर को इंजन स्पीड ट्रायल 120 किमी/घंटा की गति से किया जाएगा।

इस परियोजना को वर्ष 2022-23 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह परियोजना को 16 मई 2022 को ₹415.37 करोड़ की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई थी। इस खंड में 02 मेजर ब्रिज, 51 माइनर ब्रिज और 45 नए रोड अंडर ब्रिज (RUBs) का निर्माण किया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे लाइन को लेवल क्रॉसिंग के समीप फेंसिंग द्वारा सुरक्षित किया गया है और इस मार्ग पर कुल 04 लेवल क्रॉसिंग्स हैं।

इस ब्रॉड गेज लाइन में 60 किग्रा के नए रेल पैनल बिछाए गए हैं। आंबलियासन और विजापुर स्टेशनों को स्टैंडर्ड-II इंटरलॉकिंग सिस्टम और मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग (MACLS) के साथ आधुनिक सुरक्षा उपायों से सुसज्जित किया गया है, जिससे ट्रेनों के संचालन की सुरक्षा और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस नए ब्रॉड गेज के माध्यम से यात्रियों को अब देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बड़े शहरों से प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक, तेज और सुगम होगी।

इस गेज परिवर्तन परियोजना से यात्रियों को अब तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल यात्रा उपलब्ध होगी। इस मार्ग से उत्तरी गुजरात के ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे यात्रियों का यात्रा समय कम होगा और सुविधा में सुधार होगा। साथ ही, क्षेत्रीय व्यापार और कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस परियोजना के निर्माण और संचालन के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और समग्र क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा। नए ब्रॉड गेज कनेक्शन से भविष्य में नई यात्री और मालगाड़ियों के परिचालन की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी।

पश्चिम रेलवे की यह परियोजना यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। संरक्षा निरीक्षण के पूर्ण होने के बाद जल्द ही इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जाएगा, जिससे यात्रियों को आधुनिक, तेज और सुरक्षित रेल यात्रा का लाभ मिलेगा।

पश्चिम रेलवे वलसाड एवं हिसार के बीच चलाएगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

मुंबई,

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दिवाली एवं छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वलसाड एवं हिसार स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 04728/04727 वलसाड-हिसार साप्ताहिक स्पेशल [08 फेरे]

ट्रेन संख्या 04728 वलसाड-हिसार स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को वलसाड से 14:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 14:05 बजे हिसार पहुँचेगी। यह ट्रेन 16 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04727 हिसार-वलसाड स्पेशल प्रत्येक बुधवार को हिसार से 12:05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11.30 बजे वलसाड पहुँचेगी। यह ट्रेन 15 अक्टूबर से 05 नवंबर 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रींगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी और हांसी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04728 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे चलायेगी साबरमती-गोरखपुर और साबरमती-बेगूसराय के बीच अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा आगामी दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-गोरखपुर और साबरमती-बेगूसराय के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

- ट्रेन संख्या 09429/09430 साबरमती-गोरखपुर त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09429 साबरमती-गोरखपुर त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल साबरमती से 16 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक प्रति गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 08:50 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 10:00 बजे गोरखपुर पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09430 गोरखपुर-साबरमती त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल गोरखपुर से 17 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक प्रति शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को दोपहर 13:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन दोपहर 15:30 बजे साबरमती पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जं., अजमेर, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, दौसा, बाँदीकुई जं., भरतपुर, ईदगाह आगरा, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी,उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर एवं बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सभी अनारक्षित श्रेणी के कोच रहेंगे।

- ट्रेन संख्या 09431/09432 साबरमती-बेगूसराय अनारक्षित स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर (28 फेरे)

ट्रेन संख्या 09431 साबरमती-बेगूसराय अनारक्षित स्पेशल साबरमती से 14 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 12:05 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 08:00 बजे बेगूसराय पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09432 बेगूसराय-साबरमती अनारक्षित स्पेशल बेगूसराय से 16 अक्टूबर 2025 से 29 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 05:00 बजे साबरमती पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जं.,ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, बाँदीकुई जं., भरतपुर, ईदगाह आगरा, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिजार्पुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र जं., सोनपुर, हाजीपुर एवं बरौनी जं. स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सभी अनारक्षित श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

'उत्तराखंड का माहौल खराब कर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश...' भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कह दी बड़ी बात

उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर डेमोग्राफी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। भाजपा का कहना है कि बाहर से आकर राज्य का माहौल खराब कर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसे सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया है कि भाजपा डेमोग्राफी बदलने की मंशा से राज्य में निवासरत बाहरी लोगों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर भी पलटवार कर कहा कि लोकतंत्र में जनता ही गद्दी पर बैठाती है।

कहा कि कांग्रेस को अटकलों के बजाय 2017 और 2022 का जनादेश कांग्रेस को स्वीकारना चाहिए क्योंकि 2027 में भी यही परिणाम आने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि बाहर से आकर राज्य का माहौल खराब करने और डेमोग्राफी बदलने

की साजिश रचने वालों को लेकर सरकार की सख्ती उचित है। इस विषय से संबंधित लव जिहाद और लैंड जिहाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लव जिहाद कड़ी कार्रवाई कर चुके हैं।

हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बाहर से राज्य में आने वालों पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। राज्य के कानून के अनुसार सभी व्यक्ति भूमि क्रय विक्रय कर सकते हैं। लेकिन कोई गलत मंशा से सरकारी-गैरसरकारी भूमि कब्जे की घटनाओं में लिप्त पाए जाएंगे या राज्य के देवभूमि स्वरूप बिगाड़ने की मंशा से गतिविधियों को अंजाम देंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे सभी आपराधिक एवं शरारती तत्वों को कानूनी दायरे में कठोरतम सजा दिलाने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। ऐसे तमाम संबंधित मुद्दों पर पहले ही सरकार यूसीसी, धर्मांतरण, दंगारोधी कानूनों और अवैध धार्मिक कब्जों पर कार्रवाई से लगाम लगा रही है।

इसी तरह कालनेमी अभियान और बाहरी लोगों के सत्यापन अभियान चला कर भी राज्य से सभी ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इन तमाम विषयों पर पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है कि किसी को भी देवभूमि की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाए।

भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में इंडोनेशिया की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास 'समुद्र शक्ति'- 2025 के पांचवें संस्करण की मेजबानी करेगी

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक विशाखापत्तनम में भारत-इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, 'समुद्र शक्ति- 2025' के पांचवें संस्करण की मेजबानी कर रही है। इस अभ्यास में भाग लेने वाली इकाइयों में आईएनएस कवरत्ती, पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) के तत्वावधान में पूर्वी बेड़े का एक पनडुब्बी रोधी युद्धक कोर्वेट और इंडोनेशिया की नौसेना का पोत केआरआई जॉन लाइ, एक कोर्वेट (एक अभिन्न हेलीकॉप्टर के साथ) शामिल है। विशाखापत्तनम पहुंचने पर ईएनसी द्वारा इनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

बंदरगाह चरण में सौहार्द और पेशेवर तालमेल बनाने के उद्देश्य से जुड़ी कई गतिविधियों में क्रॉस डेक दौरे, संयुक्त योग सत्र, मैत्रीपूर्ण खेल आयोजन और पेशेवर विषय-वस्तु विशेषज्ञों का आदान-प्रदान (एसएमईई) शामिल हैं। समुद्री चरण में सामरिक समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से गतिशील और जटिल समुद्री अभियान शामिल होंगे, जिनमें हेलीकॉप्टर संचालन, वायु रक्षा अभ्यास, हथियार फायरिंग अभ्यास, दौरा, बोर्ड, खोज और जब्ती (वीबीएसएस) अभ्यास शामिल हैं।

अभ्यास 'समुद्र शक्ति' एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ को मजबूत करना और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना है। यह अभ्यास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

यूएनटीसीसी के प्रमुखों ने आगरा में एकीकृत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन देखा

(जीएनएस)।

भारतीय सेना द्वारा 14 से 16 अक्टूबर, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों (यूएनटीसीसी) के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 आज भी जारी रहा, जिसमें प्रमुखों ने एकीकृत नए युग की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन देखा।

दिन के मुख्य कार्यक्रम

यूएनटीसीसी प्रमुखों ने आगरा का दौरा किया, जहां उन्होंने एकीकृत आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन देखा, जिसमें भारतीय सेना द्वारा निर्मित नई पीढ़ी के उपकरणों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। इस प्रदर्शन ने भारत के आत्मनिर्भरता पर जोर और शांति स्थापना तथा उससे परे समकालीन संचालन चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक, नवीन और किफायती समाधान प्रस्तुत करने की उसकी क्षमता को दशार्या।

प्रतिनिधियों ने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक, ताजमहल का भी दौरा किया, जो सद्भाव और सार्वभौमिक विरासत का प्रतीक है। इसके बाद, कलाकृति हेरिटेज सेंटर का दौरा किया गया, जहां प्रतिभागियों ने भारत की कलात्मक विरासत और समृद्ध परंपराओं को दशार्ने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। इस दौरे ने कलाकारों से बातचीत करने और भारत की अनूठी विरासत शिल्पकला को देखने का भी अवसर प्रदान किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

शाम को, प्रतिनिधि लाल किले में एक प्रकाश एवं ध्वनि शो भी देखेंगे, जो भारत की सभ्यतागत यात्रा और राष्ट्रीय गौरव के मील के पत्थरों का वर्णन करेगा। यूएनटीसीसी प्रमुख दिल्ली मेट्रो से कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे, जो आधुनिकता और सतत शहरी आवागमन की दिशा में भारत की यात्रा में एक विश्व स्तरीय तकनीकी उपलब्धि है। यूएनटीसीसी प्रमुख शहरी परिवहन से लेकर सैन्य तैयारियों तक, भारत के तकनीकी प्रयासों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे, जो प्रगति, सशक्तता और वैश्विक प्रासंगिकता के समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दशार्ता है।

कॉन्क्लेव के दूसरे दिन, सांस्कृतिक पहुंच के साथ संचालन संबंधी प्रदर्शन का सफलतापूर्वक सम्मिश्रण किया गया, जिससे एक राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका सुदृढ़ हुई, जो न केवल अपनी सैन्य प्रगति के माध्यम से वैश्विक शांति और स्थायित्व की साझा आकांक्षाओं में योगदान देता है, बल्कि राष्ट्रों के बीच मैत्री के सेतु के रूप में अपनी सभ्यतागत लोकाचार और विरासत को भी प्रस्तुत करता है।

यह सम्मेलन कल अंतिम विचार-विमर्श, उद्योग के साथ बातचीत और परिणामों के सारांश के साथ संपन्न होगा, जिससे मजबूत, समावेशी और टिकाऊ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए आगे का रास्ता तय होगा।

इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 16वीं डब्ल्यू एच ओ-आई आर सी एच वार्षिक बैठक में भारत ने हर्बल औषधि विनियमन में अपनी अग्रणी भूमिका प्रदर्शित की

(जीएनएस)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन - अंतर्राष्ट्रीय हर्बल औषधि नियामक सहयोग (डब्ल्यू एच ओ-आई आर सी एच) की 16वीं वार्षिक बैठक 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में हर्बल औषधियों के विनियमन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामंजस्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विश्वभर के विनियामक प्राधिकरणों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है।

भारत ने इस बैठक में उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसमें डॉ. रघु अरक्कल, सलाहकार (आयुर्वेद) और उप महानिदेशक (प्रभारी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सक्रिया भागीदारी की। इस प्रतिनिधिमंडल ने कार्यक्रम के दूसरे दिन आयोजित तकनीकी सत्रों में प्रमुख भूमिका निभाई।

डॉ. रघु अरकल ने "हर्बल औषधियों की प्रभावकारिता और इच्छित उपयोग (कार्य समूह-3)" पर कार्यशाला रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें

पारंपरिक चिकित्सा में भारत के विकसित होते विनियामक ढाँचे और साक्ष्य-आधारित नीतिगत पहलों पर प्रकाश डाला गया।

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फामाकीपिया आयोग (पीसीआईएमएंडएच) के निदेशक डॉ. रमन मोहन सिंह ने "हर्बल औषधियों की सुरक्षा और विनियमन (कार्य समूह-1)" पर कार्यशाला रिपोर्ट प्रस्तुत की और "हर्बल औषधियों की सुरक्षा और विनियमन - भारतीय परिप्रेक्ष्य" पर एक अलग प्रस्तुति भी दी।

दोनों कार्यशालाएँ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा पीसीआईएमएंडएच के सहयोग से उनकी मेजबानी की गई थी। ये कार्यशालाएँ 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाजियाबाद में आयोजित की गई और विश्व स्वास्थ्य संगठन-आईआरसीएच बैठक के लिए प्रमुख प्रारंभिक जानकारी के रूप में कार्य किया।

इसके अलावा, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेश दाधीच ने डॉ. सिंह के साथ मिलकर "हर्बल औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण और सततता" पर एक सत्र का सह-प्रस्तुतिकरण किया। डॉ. दाधीच ने औषधीय पौधों के सतत उपयोग और गुणवत्ता नियंत्रण व मानकीकरण सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर भी विचार साझा किए।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का व्यापक योगदान हर्बल औषधियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के वैश्विक मानकों को आकार देने में भारत की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है। डब्ल्यू एच ओ-आई आर सी एच के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय विनियामक निकायों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से भारत पारंपरिक चिकित्सा और प्राकृतिक उत्पाद-आधारित स्वास्थ्य सेवा में विज्ञान-आधारित एवं सामन्जस्यपूर्ण विनियमन को बढ़ावा देता आ रहा है।

भारत की यह भागीदारी हर्बल औषधि विनियमन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने और वैश्विक मानकों को आगे बढ़ाने के लिए उसकी निरंतर प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है।

कानालुस-पोरबंदर -कानालुस लोकल ट्रेनें 30 नवंबर तक प्रभावित रहेंगी

राजकोट मंडल के लाखाबावल-पीपली-कानालुस सेक्शन में चल रहे डबलिंग कार्य के कारण 30 नवंबर, 2025 तक कानालुस-पोरबंदर और पोरबंदर-कानालुस लोकल ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

आंशिक रूप से निरस्त की गई ट्रेनें

- ट्रेन संख्या 59206 पोरबंदर-कानालुस लोकल

यह ट्रेन 16 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2025 तक पोरबंदर से प्रस्थान कर गोपजाम तक चलेगी तथा गोपजाम-कानालुस खंड के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

- ट्रेन संख्या 59205 कानालुस-पोरबंदर लोकल

यह ट्रेन 16 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2025 तक कानालुस की बजाय गोपजाम स्टेशन से चलेगी और कानालुस-गोपजाम खंड के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

यात्रियों से निवेदन

रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेनों के परिचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए यात्री वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर अवलोकन करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

चंद्रगुप्त काल के दौर से भी एतिहासिक रहे भारत-अफगानिस्तान संबंध

भारत-अफगानिस्तान संबंधों की ऐतिहासिक जड़ें बहुत गहरी हैं] अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी की भारत यात्रा ने पुरानी दोस्ती को नई जान पूंक दी है। मुत्तकी बीते गुरुवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से विस्तृत चर्चा की। यह 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान के किसी वरिष्ठ नेता की पहली भारत यात्रा है। इस मुलाकात में भारत ने काबुल में अपने पूर्ण दूतावास को फिर से सयि करने की घोषणा की, जो चार वर्षो के अंतराल के बाद एक बड़ा वूटनीतिक कदम है। मुत्तकी की यात्रा से एक उम्मीद बंधी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को 'साझा खतरा' बताया, जबकि तालिबान ने 2025 के पहलगाम हमले की निदा की। भारत-अफगानिस्तान संबंध शताब्दियों की परीक्षा से गुजरे हैं। प्राचीन बौद्ध विरासत से आधुनिक बुनियादी ढांचे तक, ये बंधन लचीले साबित हुए। मुत्तकी की यात्रा मानवतावादी सहायता को वूटनीतिक संवाद में बदलने का अवसर है। जैसे अशोक के शिलालेख आज भी बोलते हैं। दोनों देशों को आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसे साझा मुद्दों पर एकजुट होना होगा। यह न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी है, बल्कि साझा इतिहास की मांग भी। लेकिन मुत्तकी की यह यात्रा केवल वर्तमान की राजनीति नहीं, बल्कि भारत-अफगानिस्तान के गहन ऐतिहासिक बंधनों की याद दिलाती है। सिधु घाटी सयता से लेकर आधुनिक विकास परियोजनाओं तक, ये संबंध सांस्वृतिक, आर्थिक और रणनीतिक धागों से बुने गए हैं। भारत और अफगानिस्तान के संबंध प्राचीन काल से ही गहरे हैं, जब ये क्षेत्र एक सांस्वृतिक निरंतरता का हिस्सा थे। सिधु घाटी सयता (लगभग 3300- 1300 ईंसा पूर्व) के अवशेष अफगानिस्तान के उत्तरी भागों में भी मिलते हैं, जो व्यापारिक मार्गो के माध्यम से जुड़े हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय (305 ईंसा पूर्व) यह संबंध औपचारिक रूप ले चुके थे। सेल्यूकस निकेटर ने अफगान क्षेत्र मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया, बदले में 500 हाथी और वैवाहिक संबंध प्राप्त किए। सम्राट अशोक (268-232 ईंसा पूर्व) ने अफगानिस्तान को बौद्ध धर्म का वेंद्र बनाया। वंधार में उनके शिलालेख आज भी मौजूद हैं, जो धम्म के प्रचार की गवाही देते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी, इंडो-ग्रीक और वुशान साम्राज्यों ने इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप से जोड़े रखा। वुषाण शासक कनिष्क (मध्य पहली शताब्दी) ने बौद्ध धर्म को पुनजावित किया, जिसका प्रभाव गंधार कला में दिखता है। ये प्राचीन संबंध केवल राजनीतिक नहीं, सांस्वृतिक थे। अफगानिस्तान के बामियान बुद्ध (जो 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट किए गए) भारतीय बौद्ध विरासत के प्रतीक थे। व्यापार मार्गो ने मसाले, रत्न और विचारों का आदान-प्रदान सुनिाित किया, जो आज भी दोनों देशों की साझा विरासत को दशार्ता है। मध्यकाल में अफगानिस्तान भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों रहा। 10वीं शताब्दी से गजनवी, गौरी, खिलजी, लोदी और मुगल जैसे अफगान मूल के वंशों ने उत्तरी भारत पर आामण किए, जो राजनीतिक उथल-पुथल लाए लेकिन सांस्वृतिक समन्वय भी। महमूद गजनवी (998- 1030) के आव्रमणों ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, लेकिन इन्होंने फारसी साहित्य और वास्तुकला को भारत में रोपा। गौरी वंश (12वीं शताब्दी) ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो अफगान शासकों द्वारा संचालित थी। मुगल काल (1526-1858) में यह संबंध और गहरा हुआ। बाबर, अफगान मूल का था। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह दुरार्नी ने अफगान साम्राज्य स्थापित किया, जिसने पंजाब तक विस्तार किया, लेकिन महाराजा रणजीत सिह के सिख साम्राज्य ने इसे रोका। इस काल में आर्थिक लेन-देन फला-पूला। अफगानिस्तान के सूखे मेवे, घोड़े और ऊनी वस्त्र भारत पहुंचे, जबकि भारतीय वस्त्र और मसाले अफगान बाजारों में बिके। सांस्वृतिक रूप से, सूफी संतों जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (अजमेर) ने दोनों क्षेत्रों को जोड़ा। हालांकि आव्रमणों ने तनाव पैदा किया, लेकिन ये संबंध विनाशकारी नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी साबित हुए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में दो दिवसीय 'नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव' तथा 'मेयरल समिट' का शुभारंभ कराया

प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देश में सर्वप्रथम 'शहरी विकास वर्ष' जैसे कॉन्सेप्ट शुरू किए और लोगों का 'ईज ऑफ लिविंग' सुनिश्चित किया : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- कॉन्क्लेव में सरदार पटेल की शहरी विकास की तत्कालीन विचारधारा को आधुनिक विकास के साथ जोड़ने पर होगा चिंतन-मंथन
- 100 वर्ष पहले सरदार पटेल ने अपनी प्रशासनिक कुशलता से सुव्यवस्थित अर्बन प्लानिंग द्वारा आदर्श शहर का निर्माण करके देश को सिटीजन-सेंट्रिक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अनूठा मॉडल दिया
- प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अहमदाबाद ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के साथ-साथ वर्ल्ड क्लास सिटी की श्रेणी में भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया
- साबरमती रिवरफ्रंट समग्र भारत के लिए अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का एक आदर्श मॉडल बना

भारत के विभिन्न शहरों के मेयर, कमिशनर तथा प्रतिनिधि कॉन्क्लेव में उपस्थित रहे

गांधीनगर, 15 अक्टूबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को अहमदाबाद में दो दिवसीय 'नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव' तथा 'मेयरल समिट' का शुभारंभ कराया। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केन्द्र सरकार तथा अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा इस कॉन्क्लेव एवं समिट का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के 24 पूर्ण होने के अवसर पर राज्यभर में विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहली बार राजनीति में 'विकास' शब्द को सक्रिय रूप से व्यापक बनाया है।

श्री पटेल ने कहा कि यह कॉन्क्लेव एवं समिट अहमदाबाद के लिए विशेष है, कारण कि आज समग्र देश प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। ऐसे में इस कॉन्क्लेव में इस विषय पर चिंतन-मंथन किया जाएगा कि सरदार पटेल की शहरी विकास की तत्कालीन विचारधारा को आधुनिक विकास के साथ कैसे जोड़ा जाए।

अहमदाबाद के विकास में सरदार

वल्लभभाई पटेल के योगदान के ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार साहब ने 1924 से 1928 के दौरान तत्कालीन अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी की शुरूआत की थी। सरदार साहब ने लगभग 100 वर्ष पहले अपनी प्रशासनिक कुशलता तथा सुव्यवस्थित अर्बन प्लानिंग द्वारा आदर्श शहर का निर्माण कर देश को सिटीजन-सेंट्रिक लोकल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अनूठा मॉडल दिया था।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल के इन्हीं विचारों से प्रेरित रहते हुए देश में शहरी विकास में परिवर्तन से नई क्रांति लाए हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अहमदाबाद शहर ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के साथ-साथ वर्ल्ड क्लास सिटी की श्रेणी में भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।

उन्होंने आगे कहा कि अहमदाबाद का विश्व प्रसिद्ध साबरमती रिवरफ्रंट देश के अन्य शहरों के लिए अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का आदर्श मॉडल बना है। इसके अतिरिक्त; श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देश में सबसे पहली बार 'शहरी विकास वर्ष' का जो कॉन्सेप्ट दिया, वह लोगों के 'ईज ऑफ लिविंग' को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि हम उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर 2025 को 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अर्बन मोबिलिटी के बारे में कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी देश के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने शहरों के लिए सफल बीआरटीएस जनमार्ग मॉडल का विचार दिया। आज मेट्रो तथा हाईस्पीड रेल परियोजनाओं के माध्यम से मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट में अहमदाबाद अर्बन मोबिलिटी के लिए एक आदर्श बन रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले दो दशक में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में शहरीकरण का स्तर बहुत बढ़ा है और अमृत 2.0 एवं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जैसे प्रोजेक्ट्स द्वारा शहरी ढाँचे को परिवर्तित करने का कार्य हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे शहरों को विकसित भारत@2047 के अनुरूप बनाने, इनोवेशन को प्रोत्साहन देने तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा तय करने का एक सशक्त मंच बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत@2047 के लिए जो संकल्प किया है, उसे पूरा करने में यह समिट हमारे सामूहिक उद्देश्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।

उन्होंने सभी से 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ स्वदेशी को प्राथमिकता देकर प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने का माध्यम बनने का भी अनुरोध किया।

इस अवसर पर अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहमदाबाद में 'नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव' तथा 'मेयरल समिट' का आयोजन हो रहा है। यह सबके लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। श्रीमती जैन ने जोड़ा कि अहमदाबाद शहर ने शहरी विकास के क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इतना ही नहीं; विरासत की परंपरा भी अहमदाबाद ने बनाए रखी है और साथ ही कूड़े से ऊर्जा एवं ऊर्जा से अवसर का संकल्प भी अहमदाबाद ने किया है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व में अहमदाबाद शहर ने साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन (बीआरटीएस, एएमटीएस, मेट्रो), स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, शहरी हरियाली, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद की ढाँचागत सुविधाओं और विश्व स्तरीय नागरिक सुविधाओं जैसी माइलस्टोन समान पहलें की हैं। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं; इस समिट के माध्यम से भारत के शहरी परिदृश्य को एक करने, नवीनता लाने, नेतृत्व करने तथा परिवर्तन लाने के लिए लीडर्स को एक साथ लाने का प्रयास है।

बीएसएनएल ने दिवाली पर एक महीने के लिए मुफ्त मोबाइल सेवाओं का ऑफर दिया

(जीएनएस)।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) भारत की अग्रणी सरकारी दूरसंचार प्रदाता कंपनी है। इसने दिवाली के अवसर पर नए ग्राहकों को एक महीने की अवधि के लिए केवल एक रुपए के टोकन शुल्क पर 4जी मोबाइल सेवाएं देने की पेशकश की है।

यह दिवाली बोनान्जा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा।

योजना लाभ (दिवाली बोनान्जा योजना):

असीमित वॉयस कॉल (योजना नियम व शर्तों के अनुसार)

2 जीबी/दिन हाई-स्पीड डेटा

100 एसएमएस/दिन

निःशुल्क सिम (दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी)

उपरोक्त प्रस्ताव की घोषणा करते हुए बीएसएनएल के सीएमडी श्री ए. रॉबर्ट जे. रवि ने कहाः

बीएसएनएल ने हाल ही में देश भर में मेक-इन-इंडिया, अत्याधुनिक 4जी मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। दिवाली बोनान्जा प्लान—पहले 30 दिनों के लिए बिल्कुल मुफ़्त सेवा शुल्क—ग्राहकों को हमारे स्वदेशी रूप से विकसित 4जी नेटवर्क का अनुभव करने का गौरवपूर्ण अवसर प्रदान करता है। हमें विश्वास है कि सेवा की गुणवत्ता, कवरेज और बीएसएनएल ब्रांड से जुड़ा विश्वास ग्राहकों को मुफ़्त 30 दिनों की अवधि से भी आगे तक हमारे साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

दिवाली बोनान्जा योजना कैसे प्राप्त करें?

निकटतम बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएं (वैध केवाईसी दस्तावेज साथ रखें)।

दिवाली बोनान्जा प्लान (₹1 एक्टिवेशन) का अनुरोध करें; केवाईसी पूरा करें और अपना निःशुल्क सिम प्राप्त करें।

सिम डालें और उसे सक्रिय करने की प्रक्रिया निर्देशानुसार पूरी करें; आपके 30-दिन के निःशुल्क लाभ सक्रियण की तिथि से शुरू हो जाएंगे।

सहायता के लिए 1800-180-1503 पर कॉल करें या ुरल्ल'ङ्क.ल्ल पर जाएं।

आईएमएफ द्वारा भारत के विकास अनुमान को बढ़ाना देश के आर्थिक लचीलेपन और मजबूत बुनियादी कारकों का प्रमाण: श्री गोयल

रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषण के विकास में अग्रणी बनने की क्षमता, इससे भारत का वैश्विक नेतृत्व सुदृढ़ होगा: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज सीआईआई द्वारा आयोजित 7वें भारतीय रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए कहा कि रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग में नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी बनने तथा अर्थव्यवस्था एवं उद्योग के लिए अत्याधुनिक समाधान उपलब्ध कराने में भारत को अग्रणी बनाने की क्षमता है।

श्री गोयल ने रेखांकित किया कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य संतुलित विकास सुनिश्चित करना है जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ हो, घरेलू अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो और भारत वैश्विक मंच पर प्रमुखता से स्थापित हो। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत करने का उल्लेख किया, जो इसके पूर्व के 6.4 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। यह देश की आर्थिक दृढ़ता और मजबूत बुनियादी कारकों का प्रमाण है।

श्री गोयल ने इस बात पर बल दिया कि महान और उन्नत राष्ट्र प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषण पर ध्यान केंद्रित करके अपनी स्थिति प्राप्त करते हैं और भारत को अपने विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

श्री गोयल ने जोर देकर कहा कि तेल-समृद्ध देश भी मूल्यवर्धित उत्पादों, स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन-संबंधी प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रहे हैं, जो नवोन्मेषण-केंद्रित विकास की ओर वैश्विक बदलाव को दशार्ता है। उन्होंने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्रौद्योगिकीय रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता निरंतर बनी हुई है। उन्होंने विज्ञान, अनुसंधान एवं विकास तथा नवोन्मेषण के महत्व

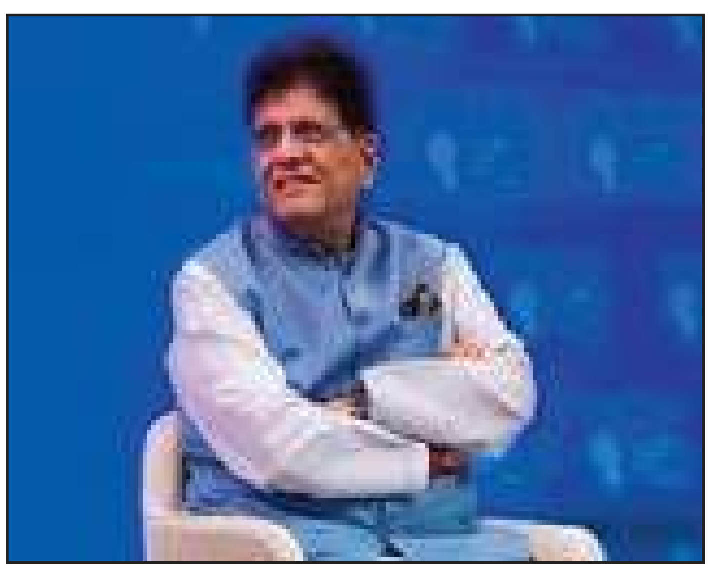

को रेखांकित करते हुए कहा कि ये भारत के एक उन्नत राष्ट्र बनने और 2047 तक विकसित भारत के विजन को अर्जित करने की यात्रा की रीढ़ हैं।

श्री गोयल ने रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्षमता और राष्ट्र के समग्र विकास में इसकी कार्यनीतिक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर का कृषि, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, निर्माण, ऊर्जा और गतिशीलता सहित कई उद्योगों में व्यापक उपयोग और प्रभाव है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र के उत्पाद और सेवाएं सर्वव्यापी हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण और उपभोग इको-सिस्टम के लगभग हर पहलू को प्रभावित करती हैं। श्री गोयल ने उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों से अपनी क्षमताओं का सावधानीपूर्वक आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने का आग्रह किया जहां भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकता है। उन्होंने इस सेक्टर के लिए वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाकर और वर्तमान मामूली योगदान से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नेतृत्व का लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। श्री गोयल ने आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन और विविधीकरण के महत्वपूर्ण महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि किसी एक आपूर्तिकर्ता या सीमित संख्या में देशों पर निर्भरता कमजोरियां पैदा कर सकती है। उन्होंने बताया कि जहां कुछ उत्पादों को आत्मनिर्भरता और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए घरेलू संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है, वहीं दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास प्राप्त करने के लिए इस सेक्टर को वैश्विक बाजारों के साथ समेकित रहना होगा।

श्री गोयल ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के लिए भारत के कार्यनीतिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी बने रहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना, व्यापार के अवसरों का पता लगाना और निवेश आकर्षित करना आवश्यक है, साथ ही वैश्विक एकीकरण और घरेलू उद्योग संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। श्री गोयल ने मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करने और भारत के वैश्विक व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने पर सरकार के निरंतर ध्यान को रेखांकित किया। उन्होंने मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन सहित कई देशों और क्षेत्रों के साथ हुए समझौतों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने बताया कि ये व्यापारिक समझौते भारतीय उत्पादों के लिए बाजार खोलने, प्रौद्योगिकी और निवेश को आकर्षित करने और नवोन्मेषण- केंद्रित सेक्टरों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि घरेलू उद्योगों को अनुचित जोखिम का सामना न करना पड़े। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य एक बेहतर संतुलन बनाना है, जिसमें भारतीय व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना तो है ही, साथ ही घरेलू उत्पादन की रक्षा करना और 140 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी है। श्री गोयल ने कहा कि यद्यपि सरकार वैश्विक एकीकरण चाहती है, फिर भी वह बाजार की गतिशीलता, आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन तथा निष्पक्ष एवं टिकाऊ व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के प्रति सजग है, जिससे उद्योग और अंतिम उपभोक्ता दोनों को लाभ हो।

श्री गोयल ने उद्योग जगत के प्रतिभागियों से सहयोगात्मक रूप से कार्य करने, मूल्य श्रृंखलाओं में एक-दूसरे की सहायता करने और निर्यात को प्रभावित करने वाली शोषणपूर्ण मूल्य निर्धारण, डंपिंग या गैर-टैरिफ बाधाओं के बारे में चिंताएं व्यक्त करने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्रालय उद्योग जगत के हितों की रक्षा के लिए समय पर युक्तियां और समाधान प्रदान करेगा।

निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों के लिए मतदान को आसान बनाने हेतु निर्देश जारी किए

(जीएनएस)।

निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चुनाव दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सुलभ हों।

बिहार में, सभी मतदान केंद्र भूतल/सड़क प्रवेश स्तर पर स्थित होंगे और दिव्यांग मतदाताओं और व्हीलचेयर वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उचित ढलान वाले रैंप होंगे। यह निर्देश भी दिया गया है कि दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्रों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाए।

आयोग ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए नियमित मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) के साथ-

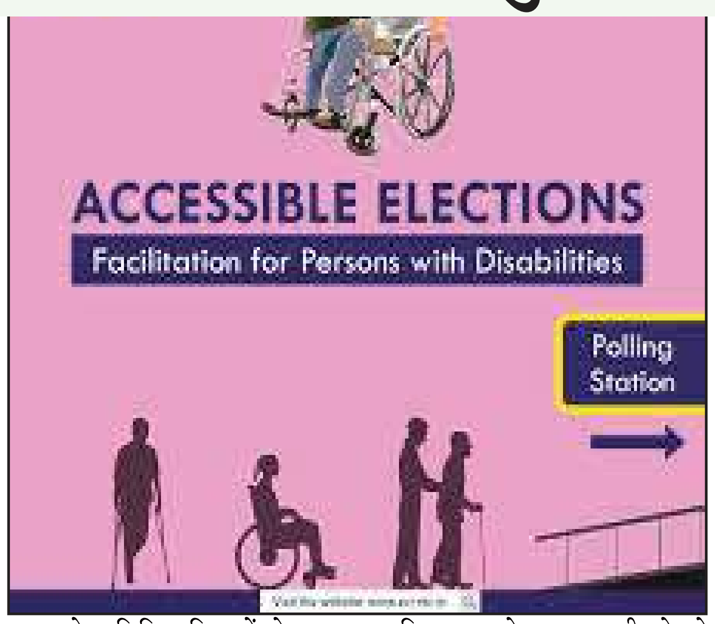

साथ ब्रेल लिपि सुविधाओं के साथ सुगम्य मतदाता सूचना पर्चियां जारी करने का निर्देश दिया है।

निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49एन के अनुसार, दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अपनी ओर से वोट डालने के लिए अपने साथ एक सहयोगी को ले जा सकते हैं।

सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कोई भी दृष्टिबाधित मतदाता बिना किसी सहयोगी की मदद के ईवीएम की बैलेट यूनिट पर ब्रेल लिपि सुविधा का उपयोग करके स्वयं इस शीट का उपयोग करके अपना वोट डाल सकता है।

आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र पर दिव्यांगजनों के लिए उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। दिव्यांग मतदाता ईसीआईएनईटी के दिव्यांग (सक्षम) मॉड्यूल पर पंजीकरण कराकर परिवहन और व्हीलचेयर सुविधा का अनुरोध भी कर सकते हैं।

ये सुविधाएं बिहार के 90 हजार 712 मतदान केंद्रों में से प्रत्येक पर उपलब्ध होंगी। एक अन्य पहल के अंतर्गत 292 मतदान केंद्रों का प्रबंधन विशेष रूप से दिव्यांगजनों द्वारा किया जाएगा।

आगामी बिहार चुनावों में धनबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए

चुनाव व्यय पर निगरानी रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की।

आगामी चुनावों में धनबल, मुफ्तखोरी के साथ-साथ ड्रग्स, नशीले पदार्थों और शराब के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए, आयोग ने राज्य पुलिस विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, आयकर विभाग, एफआईयू-आईएनडी, आरबीआई, एसएलबीसी, डीआरआई, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीमा शुल्क, ईडी, एनसीबी, आरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीसीएएस, एएआई, डाक विभाग, राज्य वन विभाग और राज्य सहकारिता विभाग सहित सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं।

उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनावी खर्च की निगरानी रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षकों को पहले ही तैनात कर दिया गया है और वे चुनाव की अधिसूचना जारी होने के दिन ही अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। इस दौरान वे व्यय निगरानी में लगी सभी टीमों से मिलेंगे।

मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन-बल या अन्य प्रलोभन के किसी भी संदिग्ध मामले पर नजर रखने के लिए उड़न दस्ते, निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल चौबीसों घंटे सतर्क रहेंगे।

आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान वास्तविक समय के आधार पर एफ.एस, एस.एस.टी. और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए अवरोधन/जब्ती की रिपोर्टिंग के लिए चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ई.एस.एम.एस.) नामक ऑनलाइन प्रणाली को भी सक्रिय किया है।

6 अक्टूबर, 2025 को चुनावों की घोषणा के बाद से, विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कुल 33.97 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स और निःशुल्क उपहार जब्त किए गए हैं।

आयोग ने इस बात पर भी बल दिया कि प्रवर्तन प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निर्देशों के प्रवर्तन के लिए जांच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को असुविधा या परेशानी न हो।

कोई भी आम नागरिक सी-विजिल ऐप के माध्यम से ऐसे किसी भी उल्लंघन के संबंध में शिकायत कर सकता है।

पार्षद नईम ने ताजी खाना में खराब समरसेबल तुरंत लगवाकर दी राहत

ताजी खाना में पानी संकट खत्म, पार्षद नईम ने समरसेबल खराब होते ही तत्काल लगवाया,

(जीएनएस)।

लखनऊ। वजीरगंज-मशकगंज वार्ड संख्या 102 में, पार्षद मोहम्मद नईम ने सेवा की एक नई मिसाल कायम की है। लगातार पाँच बार जीतने के बाद, उन्होंने छठी बार भी जीत हासिल की है, जिससे यह साबित होता है कि उनका और उनके परिवार

का राजनीतिक सफर सन 1995 से निरंतर जारी है।

25 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय, नईम भाई की पहचान उनका कार्य है। वह अपने कार्यालय को सेवा केंद्र मानते हैं, जहाँ वह सुबह 8 से 2 और शाम 5 से 8 बजे तक जनता की समस्याएं सुनते हैं और उनका तुरंत निस्तारण करते हैं।

हाल ही में, ताजी खाना क्षेत्र में समरसेबल खराब होने की सूचना मिलते ही, उन्होंने तत्काल नया समरसेबल लगाने का आदेश दिया और टीम को मौके पर भेजा ताकि लोगों को परेशानी न हो।

छात्र राजनीति से जनसेवा में उतरे नईम भाई का मानना है कि राजनीति लोगों के लिए काम करने का माध्यम है। उनकी पत्नी, साइमा नईम, जो वर्तमान में इसी वार्ड से सपा पार्षद हैं, भी इसी सेवा भावना के लिए जानी जाती हैं। मोहम्मद नईम की लगातार जीत यह दशार्ती है कि लखनऊ नगर निगम में काम बोलता है'।

डिवाइन डेंटल केयर क्लीनिक का उद्घाटन : एमएलसी अवनीश कुमार सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन

लखनऊ / आलमबाग गीता पल्ली मार्केट में डिवाइन डेंटल केयर क्लीनिक का उद्घाटन लखनऊ क्लीनिक खुलने से यहां के आसपास के लोगों के लिए काफी सुविधाजनक एवं लाभदायक होगा तथा इस में किया जाएगा तथा डिवाइन डेंटल केयर की तरफ से प्रत्येक मंगलवार के दिन मरीजो के लिए यह सुविधा कम पैसों में इलाज किया जा सके।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से एमएलसी स्नातक अवनीश कुमार

स्नातक एमएलसी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा किया गया क्लीनिक की मुख्य चिकित्सक डॉक्टर कीर्ति सिंह भी मौजूद रही क्लीनिक का उद्घाटन करने के बाद मुख्य अतिथि एमएलसी स्नातक लखनऊ अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में दांत क्लीनिक मे दांत से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का निदान किया जाएगा।

डिवाइन डेंटल केयर की मुख्य चिकित्सा डा कीर्ति सिंह ने बताया कि यहां पर दांत की गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज कम से कम शुल्क उपलब्ध रहेगी निःशुल्क कैंप भी लगाया जाएगा जिसके माध्यम से गरीब व्यक्तियों का निःशुल्क दंत से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा डॉ कीर्ति सिंह ने बताया कि क्लीनिक का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का कम से सिंह राष्ट्रीय लोकदल प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष अंबुज पटेल हाई कोर्ट अधिवक्ता, पंकज कुमार, मनीष पटेल, सुमित सिंह, अश्वनी प्रताप सिंह, आर के पटेल, प्रबंधक एसके सिंह एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे

गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस ने उत्तर भारत में अपनी मौजूदगी का विस्तार किया

वित्त वर्ष 2026 तक स्वास्थ्य बीमा की पहुँच बढ़ाने का लक्ष्य लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय की शुरूआत;

राज्यभर में 1,000 एजेंट जोड़ने और 5,000 लोगों को बीमा सुरक्षा देने की योजना

स लखनऊ, 15 अक्टूबर 2025: भारत की सबसे नई स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनी, गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस — जिसे टीव्हीएस समूह के श्री वेणु श्रीनिवासन और बीमा क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री वी. जगन्नाथन के परिवार का सहयोग प्राप्त है — ने आज उत्तर भारत में अपने विस्तार की घोषणा की। इसके तहत कंपनी ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किया है। यह कदम पूरे देश में किफायती और सबके लिए सुलभ स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की दिशा में कंपनी की बड़ी योजना का हिस्सा है। गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस का उद्देश्य राज्यभर में समावेशी स्वास्थ्य समाधान का विस्तार कर 5,000 लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। उत्तर भारत में विस्तार की रणनीति के तहत, कंपनी वित्त वर्ष 2026 तक उत्तर प्रदेश में 1,000 से अधिक एजेंट जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे ग्रामीण और कम सेवा-प्राप्त परिवारों तक बीमा सेवाएं पहुँचाई जा सकें। गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री जी. श्रीनिवासन ने कहा, ह्लउत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा की पहुँच बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं। लखनऊ में हमारी उपस्थिति के साथ, हम उत्तर भारत के लोगों को किफायती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस का उत्तर प्रदेश बाजार में प्रवेश एक समयोचित और सार्थक कदम है, जिसका उद्देश्य कमजोर और सीमित आर्थिक पहुँच वाले परिवारों को औपचारिक वित्तीय सुरक्षा प्रणाली से जोड़ना है। हमारी सोच सादगी और समावेशन पर आधारित है — ताकि ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवार भी वह देखभाल और सुरक्षा पा सकें जिसके वे हकदार हैं ह्व गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस को मार्च 2024 में क्रक्रऊअक से संचालन लाइसेंस प्राप्त हुआ था। अपने पहले ही वर्ष में कंपनी ने देशभर में 12,000 से अधिक एजेंटों का नेटवर्क बनाया और 1.85 लाख से अधिक लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान की। कंपनी की प्रमुख बीमा योजनाओं में शामिल हैं: ड्ट गैलेक्सी प्रॉमिस – परिवारों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना ड्ट गैलेक्सी मार्वेल – एक अनुकूलन योग्य योजना जो व्यापक पारिवारिक कवरेज प्रदान करते हुए स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहन देती है और परिवार को संपूर्ण कवरेज प्रदान करती है।

कलर्स के 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा – जोडियों का रियलिटी चेक' पर फराह खान और दिलीप मुखिया ने नए जोड़े की पहली रसोई को बनाया मजेदार

कलर्स के 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा – जोडियों का रियलिटी चेक' पर अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की भव्य शादी एक परफेक्ट बॉलीवुड फेयरीटेल की तरह सजी। भावनाओं से भरे दिल, प्यार से सराबोर लम्हे और जश्न का अद्भुत रंग – सब मिलकर इस टीवी शादी को अविस्मरणीय बना देते हैं! ठीक तभी, जब नवविवाहित जोड़ा अपने इन जादुई पलों का आनंद ले रहा होता है, मंच पर प्रवेश करती हैं मल्टी-टैलेंटेड फिल्ममेकर फराह खान। अपने खास अंदाज, 'ूमर और स्वाद के तड़के के लिए जानी जाने वाली फराह खान अपने घर के बने स्पेशल पकवान के बिना कभी कहीं नहीं जातीं, और सभी को अपने स्वादिष्ट व्यंजनों से लुभाती हैं। और इस बार वे अकेली नहीं हैं, उनके साथ हैं उनके भरोसेमंद कुक – दिलीप मुखिया। तैयार हो जाइए उस मजेदार नोक-झोंक के लिए, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों से हो रही है! दोनों मिलकर शो पर आते हैं, नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हैं और अविका-मिलिंद की पहली रसोई को पति-पत्नी के रूप में यादगार बनाते हैं, मंच को हंसी, प्यार और मसाले का संगम कर देते हैं।

लेकिन मस्ती यहीं खत्म नहीं होती! मजा दोगुना हो जाता है, जब फराह बाकी कंटेस्टेंट्स की कुकिंग स्किल्स की परीक्षा लेने का फैसला करती हैं। वे स्वरा और फहद को वड़ा बनाने का टास्क देती हैं, और गड़बड़ी शुरू हो जाती है। वड़े में छेद करना भूल जाने से दोनों की हालत हास्यास्पद हो जाती है, और अचानक फहद फराह की किसी आइकॉनिक फि ल्म का गाना गाने लगते हैं। किचन ठहाकों और मस्ती से गूंज उठता है, यह साबित करते हुए कि जहां फराह खान होती हैं, वहां कभी बोरियत नहीं हो सकती। अपने जोशीले अंदाज और खाने के प्रति प्यार के साथ फराह ने भरपूर धमाल मचाया! क्या अविका अपनी पहली रसोई की परीक्षा शानदार तरीके से पास करेंगी? जानिए सिर्फ. कलर्स के 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा – जोडियों का रियलिटी चेक' में।

निविया बॉडी मिल्क प्रस्तुत करता है 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा – जोडियों का रियलिटी चेक', को-पॉवर्ड बाय शुगर फ्री ग्रीन, कैडबरी डेयरी मिल्क, पोर होम एयर फ्रेशनर्स, एन्वी परफ्यूम्स, लॉरियल पेरिस हायलूरॉन प्योर और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। स्पेशल पार्टनर्स: कोलगेट और एचडीएफसी लाइफ। देखें हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे, सिर्फ कलर्स पर।

डीपीए के पदाधिकारियों ने ग्रहण की शपथ

लखनऊ। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन (डीपीए) की जनपद इकाई की नयी कार्यकारिणी गठित की गयी। चुनाव प्रक्रिया प्रांतीय पर्यवेक्षक एवं डीपीए के प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय पांडेय की देखरेख में सम्पन्न की गयी, जिनमें डीपीए जनपद शाखा बाराबंकी के अध्यक्ष पद पर केके सिंह और मंत्री राकेश कुमार तिवारी निर्वाचित हुए। सभी आठ पदों पर चुनाव में विजयी रहे प्रत्याशियों को प्रांतीय पर्यवेक्षक अजय पांडेय ने पद एवं

गोपनीयता की शपथ दिलायी। इसके बाद सभा को सम्बोधित करते हुए श्री पाण्डेय ने कहा कि संवर्ग की समस्याओं का निराकरण कराने के साथ ही हमारा समाजिक दायित्व भी है। हाल ही में विभिन्न राज्यों में बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हुई, जो मिलावटी कफ सिरप के सेवन के कारण हुई। इस पर निजी क्षेत्र के फाम्रेसी साथियों को पत्र देकर अपील की गयी कि बिना डाक्टर की लिखी कोई दवा न बेंचे। उन्होंने आगे कहा कि दीपावली का पर्व नजदीक है और हर वर्ष की भांति अनाथ बच्चों को उपहार देते हैं। इसकी रूपरेखा शनिवार को बलरामपुर अस्पताल में एसोसिएशन के कार्यालय में बैठक के दौरान तय की जाएगी।

बलरामपुर अस्पताल प्रशासन करा रहा जांच -शिकायतकर्ता, आरोपी सुपरवाइजर व कंपनी से दस्तावेज मांगे

लखनऊ, बलरामपुर अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारी से घूसखोरी के मामले की जांच शुरू हो गई है। वार्ड ब्वॉय का काम कर रहे कर्मचारी को सुरक्षाकर्मी बनाने की धमकी देकर 40 हजार रुपये वसूली की शिकायत हुई थी। इस मामले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने शिकायतकर्ता, आरोपी व आउंटसोर्सिंग कंपनी से जरूरी दस्तावेज तलब किए हैं। इसके लिए दो दिन की मोहलत दी गई है।

बलरामपुर अस्पताल में 756 बेड हैं। ज्यादातर बेड हमेशा भरे रहते हैं। प्रतिदिन पांच से सात हजार मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी भी अस्पताल में तैनात हैं। लेकिन इन कर्मचारियों को वसूली के लिए परेशान करने के गंभीर आरोप लगे हैं। कई वर्षों से वार्ड ब्वॉय का काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी का आरोप है कि सुपर वाइजर परेशान कर रहे हैं। आरोप है कि कर्मचारी को

वार्ड ब्वॉय का काम लेकर सुरक्षा गार्ड बनाने की धमकी दी गई। ऐसा न करने के एवज में वार्ड ब्वॉय से 40 हजार रुपये वसूले। पीड़ित ने आरोपी से 40 हजार रुपये वापस दिलाने व कठोर कार्रवाई की फरियाद की है।

अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। मामले की जांच कराई जा रही है। इस संबंध में शिकायतकर्ता, आरोपी व आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। कंपनी से शिकायतकर्ता की तैनाती किस पद पर हुई? इससे संबंधी दस्तावेज मांगे हैं। वहीं शिकायतकर्ता ने कमेटी को शपथ पत्र पर अपना बयान दर्ज कराया है। जांच कमेटी ने आरोपी से हाजिरी समेत दूसरे रजिस्टर व दस्तावेज मांगे है। निदेशक डॉ. कविता आर्या का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आरोपी सुपरवाइजर से काम नहीं लिया जा रहा है। जल्द ही जांच पूरी करने के निर्देश कमेटी को दिए गए हैं।

दीपोत्सव व अन्य त्योहारों में उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बैठक में आरटीओ अयोध्या ने दिये निर्देश

अयोध्या , माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय परिवहन मंत्री महोदय के निर्देशों के क्रम में आगामी त्योहारों व अयोध्या में संपन्न होने वाले दीपोत्सव जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं, अति-विशिष्ट विभूतियों एवं पर्यटकों के आना संभावित है, के दृष्टिगत उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु आरटीओ प्रशासन सुश्री ऋतु सिंह ने मण्डल के पाँचों जनपदों- अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी व बाराबंकी के एआरटीओ प्रशासन प्रवर्तन एवं यात्रीकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।बैठक में सर्वोच्च प्राथमिकता पर सभी कामर्शिएल वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, पीयूसी, टैक्स आदि प्रपत्रों को अद्यतन वैध करवाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश अधीनस्थों को आरटीओ ने दिये। उन्होनें नोटिस, सोशल मीडिया व अखबारों आदि के माध्यम से इस संबंध में जागरूकता एवं संबंधित को सूचित करने को कहा और साथ ही प्रभावी चेकिंग की जाय ताकि एक भी अनफिट गाड़ी सड़क पर संचालित न होने पायें। ट्रांसपोटर्स के साथ बैठकें कर बताय जाय कि यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार और अधिक किराया न लिया जाय, माल गाड़ी में यात्री न ढोये जाय। साथ ही आँकलन कर लिया जाय कि अयोध्या जनपद में अन्य शहरों से कितने यात्रीगण बसों, गाड़ियों से आएंगें एवं तदानुसार सुव्यवस्थित यातायात हेतु पुलिस विभाग का सहयोग करें।

आरटीओ द्वारा संभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अक्टूबर माह के अवशेष दिनों में युद्ध स्तर पर मल्टीफोकस कार्यवाही करते हुये राजस्व की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें एवं बकाया, बिना परमिट या परमिट समाप्त वाहनों, निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग सरेण्डर वाहनो के सत्यापन आदि पर कड़ी प्रवर्तन कार्यवाही करें एवं साप्ताहिक सूचना उपलब्ध करायें। कार्यालय में पारदर्शिता स्थापित करने और कार्यालय के बाहर दुकानों की जाँच जिला प्रशासन से अनुरोध कर करवाने के निर्देश भी दिये गये।

आयुक्त महोदय अयोध्या मण्डल के निर्देशों के क्रम में शत-प्रतिशत स्कूली वाहनों की फिटनेस की जाँच कर ली जाय व स्कूल परमिट हेतु मानक पूर्ण होने के साथ ही उ०प्र० मोटरयान नियमावली एवं शिक्षा के व्यावसायीकरण में गठित मा० विधान परिषद द्वारा दिये गये निर्देश में विहित व्यवस्था पूर्ण करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों के स्कूल परमिट हेतु संस्तुति प्रेषित करें और अनाधिकृत संचालन परमिट शर्तों के उल्लंघन में भी कार्यवाही की जाय। निर्देश दिये कि शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर स्कूली वाहनों से संबंधित सभी नियमों का कड़ाई से अनुपालन करायें।

बैठक में आरटीओ प्रशासन अयोध्या ऋतु सिंह, एआरटीओ अमेठी श्री महेन्द्र बाबू, श्रीमती अंकिता शुक्ला, श्री आर.पी. सिंह, श्री सत्येन्द्र यादव, सुश्री अल्का शुक्ला, पीटीओ श्री शैलेन्द्र तिवारी व श्री दिनेश रावत उपस्थित रहें।

(ऋतु सिंह)

नक्सल मुक्त भारत बनाने के मोदी सरकार के संकल्प की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर सिर्फ 3 रह गई

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 18 से घटकर केवल 11 रह गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इन अभियानों में 312 छहए कैडर मार गिराए गए हैं

836 छहए कैडरों को गिरफ्तार किया गया है और 1639 ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण किया

मोदी सरकार में बहुआयामी दृष्टिकोण आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना और नीति को कठोरता से लागू कर नक्सल खतरे से निपटने में अभूतपूर्व सफलता मिली है

मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कटिबद्ध

(जीएनएस)।

नक्सल मुक्त भारत बनाने के मोदी सरकार के संकल्प की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर सिर्फ 3 रह गई है। अब केवल छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही वामपंथी उग्रवाद (LWE) से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या भी 18 से घटकर

केवल 11 रह गई है। इस प्रकार अब केवल 11 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन अभियानों में 312 वामपंथी कैडरों को मार गिराया गया है, जिनमें सीपीआई (माओवादी) महासचिव और पोलित ब्यूरो/केन्द्रीय समिति के 08 अन्य सदस्य शामिल हैं। 836 वामपंथी कैडरों को गिरफ्तार किया गया है और 1639, जिनमें एक पोलित ब्यूरो सदस्य और एक केन्द्रीय समिति सदस्य शामिल हैं, ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण किया है।

मोदी सरकार में बहुआयामी दृष्टिकोण आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना और नीति को कठोरता से लागू कर नक्सल खतरे से निपटने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। राष्ट्रीय कार्य योजना और नीति में जन-हितैषी छहए अभियानों पर आधारित सटीक आसूचना शामिल है। इन कदमों में सुरक्षा वेक्यूम वाले क्षेत्रों में त्वरित डॉमिनेशन, शीर्ष नेताओं और ओवर ग्राउन्ड कार्यकताओं को निशाना बनाना, कुटिल विचारधारा का मुकाबला करना, बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास और कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह लागू कराना, वित्तीय संसाधनों को पूरी तरह बंद करना, राज्यों एवं केन्द्र सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, और माओवादी संबंधित मामलों की त्वरित जांच और अभियोजन शामिल हैं।

वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा जिसे भारत की "सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती" कहा गया, वह नक्सलवाद अब स्पष्ट रूप से पीछे हट रहा है। नक्सलियों ने नेपाल के पशुपति से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक एक लाल कोरिडोर स्थापित करने की योजना बनाई थी। वर्ष 2013 में विभिन्न राज्यों के 126 जिलों में नक्सल-संबंधी हिंसा रिपोर्ट की गई थी, जबकि मार्च 2025 तक यह संख्या घटकर केवल 18 जिलों तक सीमित रह गई थी और इनमें से केवल 06 'सबसे अधिक प्रभावित जिले' की श्रेणी में थे।